

time. Owing to the increasing costs, however, the management found itself obliged to increase the rates in June, 1966. The approval of the Department of Tourism was obtained before this was done. This decision was not connected with the devaluation of the rupee.

जाओरा रेलवे स्टेशन पर ग्रफीम का पकड़ा जाना

4088. श्री युद्धवीर सिंह :

श्री बड़े :

श्री हुकूम चन्द कड़वाय :

श्री जगदेव सिंह तिडानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जुलाई, 1966 के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित यह समाचार सच है कि जाओरा रेलवे स्टेशन पर लगभग दस हजार रुपये मूल्य की 14 किन्तों ब्रकम पकड़ी गई ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक ।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, संस्था में दाखिला

4089. डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री रामलोक यादव

श्री मधु लिये :

श्री किशन पटनायक :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन वर्ष अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में

विद्यार्थियों के दाखिले का प्रगालो में कुछ परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री

(डा० सुशीला नायर) : (क) छात्रों को दाखिले की प्रगालों में इन वर्ष कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Representation from Akhila Kerala Vishwa Karma Maha Sabha

4090. Shri Vasudevan Nair: Will the Minister of Planning and Social Welfare be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister received any memorandum from Akhila Kerala Vishwa Karma Maha Sabha during her recent tour of Kerala State; and

(b) if so, the action taken on the points raised therein?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) and (b). The Akhila Kerala Vishwa Karma Maha Sabha had submitted a Memorandum to the Prime Minister asking for educational concessions and reservations in services, educational institutions and in the State Legislature. As far as the Government of India are concerned, it has already been decided that the Other Backward Classes should be defined on the basis of an economic criterion. Since the Vishwa Karma community in Kerala is treated as Other Backward Classes on the basis of caste, it is primarily for the State Govt. to consider the nature and extent of the concessions to be allowed to the Other Backward Classes in the State. Their request for reservation in the State Legislature is not however tenable as the Constitution provides for reservation only for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.